

फर्जी दस्तावेजों से मान्यता लेने वाले छह कॉलेजों पर एफआईआर के बाद एसटीएफ ने बनाए जांच दल

सिटी चीफ भोपाल।

कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बीएड व डीएड पाठ्यक्रम की मान्यता लेने वाले कॉलेजों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के बाद अब मप्र स्पेशल टॉक फोर्स (एसटीएफ) ने प्रत्येक कालेज की जांच के लिए एक टीम बना दी है। टीम कालेजों से दस्तावेज लेकर जांच करेगी और कालेज संचालकों से पूछताछ की जाएगी। बाद में विशेषज्ञों का दल बनाकर भी दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाएगा। इससे साफ होगा गडबड़ी किस स्तर पर हुई है। किन्तु दस्तावेज फर्जी लगाए गए हैं। एसटीएफ को नियमों से शिकायत की थी कि कुछ कॉलेजों ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीईई) और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को कूटरचित दस्तावेज दिखाकर



मान्यता ले ली है। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर एसटीएफ ने इस मामले में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। जिन कॉलेजों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें अंजुमन कॉलेज आफ एजुकेशन सेवा (दिल्ली), प्राशी कॉलेज

ऑफ एजुकेशन मुंगावली (अशोकनगर), सिटी पब्लिक कॉलेज, शाडौरा (अशोकनगर), मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, वीरपुरु (श्योपुर), प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा (श्योपुर) और आइडियल टीवारी के नेतृत्व में गठित दल ने पूरे मामले की जांच की है।

नाबालिग पर जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाश गिरपतार, गांजा तस्करी की फिराक में घूम रहे थे

सिटी चीफ भोपाल।

ऐश्वर्य पुलिस ने 17 साल के किशोर पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले बदमाश शरीफ बंचा और एक अन्य बदमाश अमिर मुर्गी को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों गांजा तस्करी की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने उनके एक किलो × 00 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एस्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 29 मई को मुख्यमंत्री की सूचना पर गुरुनानकपुरा बिजली की ढीपी के पास ऐश्वर्य से



स्कूटर सवार दो लड़कों को घेरावंदी कर दबोचा। तलाशी में उनके पास से एक किलो × 00 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा

रखा मिला। उनकी पहचान अमिर उर्फ मुर्गी (28) निवासी छोटा चंबल सुदमा नगर ऐश्वर्य व शरीफ कुरैशी उर्फ बंचा (×4)

30 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे

सिटी चीफ भोपाल।

मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम में 30 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले स्कूलों के शिक्षकों पर जारी चल रही है। इससे पहले 2022 में लोक शिक्षण संचालनालय (डीडीआर) ने 30 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले नियमित शिक्षकों की परीक्षा आयोजित कराई थी। इसी को देखते हुए कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (डीडीओ) ने कार्रवाई शुरू कर दिया है इनमें कुछ जिलों में अतिथि शिक्षकों को भी नहीं पढ़ाने के अदेश जारी किए जा रहे हैं। रायसेन, दमोह सहित अन्य जिलों के डीडीओ ने आदेश जारी किए थे। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 72 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। इन पदों पर हर साल अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं। इनमें कुछ जिलों में



अतिथि शिक्षकों को भी नहीं पढ़ाने के अदेश जारी किए जा रहे हैं। रायसेन, दमोह सहित अन्य जिलों के डीडीओ ने आदेश जारी किए थे। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 72 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। इन पदों पर हर साल अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं। इनमें कुछ जिलों में

अगर बोरवेल खुला छोड़ा तो आपकी खैर नहीं

कड़े कानून को लाने की तैयारी मानसून सत्र में होगा पेश

सिटी चीफ भोपाल।

आपांग पर बोरवेल से पानी नहीं निकलने पर उसे खुला ही छोड़ दिया जाता है। खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। बोरवेल खुला छोड़ने और बच्चों के गिरने की हालिया घटनाओं को देखते हुए पहली बार मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनाया जा रहा है। इसे जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करने की तैयारी है। इसमें खुला बोरवेल छोड़ने पर भूमि स्वामी पर अर्थदंड लाने का प्रविधान होगा। जननानि की स्थिति में आपाराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही, बोरिंग करने वाली एजेंसी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ताकि बोरवेल असफल हो तो वह अनिवार्य रूप से बंद करे। लोक स्वास्थ्य योग्यता विभाग ने विधेयक का प्रारूप तैयार कर दिया है। कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इससे वरिष्ठ सचिव समिति की हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।



को बंद नहीं करने के कारण कई बच्चों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। घंटों राहत कार्य चलाने के बावजूद कई प्रकरणों में बच्चों की जान चली गई। शिवराज सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्र ने जून 2022 में आरक्ष के नारायणपुरा में बोरवेल में चार वर्ष के दीपेंद्र के गिरने की घटना के बाद खुले बोरवेल को नियन्त्रित करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद कई घटनाएं हो गईं पर कानून नहीं बन पाया। जबकि, सुमीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट प्रविधान करने के लिए एक दल बनाए।

विकास विभाग ने दिशानिर्देश जारी किए पर इनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रविधान हैं, उनके अनुसार कार्रवाई की जाती है। खुले बोरवेल को बंद न करने और किसी के उसमें गिरने पर कार्रवाई का कोई प्रविधान नहीं है। इसके लिए पहली बार कानून बनाया जा रहा है। इसमें खुला बोरवेल छोड़ने पर भूमि स्वामी पर अर्थदंड और जनहनिन पर अन्य विधेयक दर्ज करने का प्रारूप दर्ज करने का प्रविधान प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रयास होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है।

आरजीपीवी घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच, विश्वविद्यालय से मांगे दस्तावेज

सिटी चीफ भोपाल।

शहर में स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में हुए 19.48 करोड़ के एफएडी घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. सुनील कुमार के कार्यकाल के बैंक खातों की जानकारी युनिवर्सिटी से मांगी है। ईडी ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय को घोटाले के नेतृत्व में गठित दल ने पूरे मामले की जांच की है।

सिटी चीफ भोपाल। अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के खातों में जमा 19.48 करोड़ रुपये की राशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी थी। विश्वविद्यालय के खातों में जमा यह रकम निजी खातों में ट्रांसफर करने के साथ और किस-किस तरह की गडबड़ी की जांच की है। बता दें कि कुलपति व अन्य

तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक सहित आठ लोगों के खातों में जमा 19.48 करोड़ रुपये की राशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी थी। मामले में कुलपति से इसीकाले ले लिया गया था। तत्कालीन कुलपति समेत कुछ अपार्टमेंटों की गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हुई हैं।

तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक सहित आठ लोगों के खातों में जमा 19.48 करोड़ रुपये की राशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी थी। विश्वविद्यालय की आपार्टमेंटों में जमा यह रकम निजी खातों में ट्रांसफर करने के साथ और किस-किस तरह की गडबड़ी की जांच की है। बता दें कि इस मामले में अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के खातों में यह पारंपरिक रूप से विश्वविद्यालय के खातों में जमा रखा गया था। तत्कालीन कुलपति समेत कुछ अपार्टमेंटों की गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हुई हैं।

तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक सहित आठ लोगों के खातों में जमा 19.48 करोड़ रुपये की राशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी थी। विश्वविद्यालय की आपार्टमेंटों में जमा यह रकम निजी खातों में ट्रांसफर करने के साथ और किस-किस तरह की गडबड़ी की जांच की है। बता दें कि इस मामले में अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के खातों में यह पारंपरिक रूप से विश्वविद्यालय के खातों में जमा रखा गया था। तत्कालीन कुलपति समेत कुछ अपार्टमेंटों की गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हुई हैं।

तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक सहित आठ लोगों के खातों में जमा 19.48 करोड़ रुपये की राशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दी थी। विश्वविद्यालय की आपार्टमेंटों में जमा यह रकम

साम्पदकीय

हजारों मेडिकल छात्रों को कोर्स या दुनिया छोड़ने की नौबत क्यों आ रही?

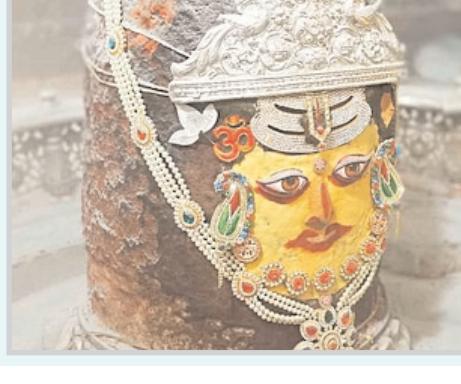
मेडिकल छात्रों की आत्महत्या हमारे देश में मामूली बात है। तमाम समस्याओं के बीच इस पर ध्यान देने की फूसत किसी को नहीं। यही कारण है कि देहरादून में शिशुरोग के पीजी मेडिकल छात्र डॉ. दिवेश गर्ग की आत्महत्या भी महज एक संख्या बाकर रह गई।

पलवल (हरियाणा) के एक मध्यवर्तीय परिवार ने जिंदगी भर की कमाई दाव पर लगाया 38 लाख रुपये देकर बेटे का एडमिशन कराया था। पूरे कोर्स पर लगभग 1.20 मिलार्ड का खर्च आता। लेकिन 17 मई की रात उसने कॉलेज के होस्टल में आत्महत्या कर ली। चार बहनों का इकलौता भाई था। शोककुल पिता कहते हैं- क्या कहें भाई, हमारी तो जिंदगी ही लुट गई नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने आरटीआई के तहत डॉ. दिवेश गर्ग की संख्या एक सौ पचासवाँ होगी। यह संख्या कृच कम या अधिक हो सकती है।

मध्यवर्तीय परिवारों के बच्चों का एमबीबीएस कर लेना एक बड़ा सपना होता है। इसके बाद पीजी में बेहद कम सीटें होने के कारण एडमिशन काफी मुश्किल समझा जाता है। लेकिन वर्ष 2018 से 2022 के बीच 1270 मेडिकल छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। इसमें पीजी छात्रों की संख्या 1117 है। यह बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। ऐसे छात्रों के समने दुनिया छोड़ देने अथवा पढ़ाई छोड़ देने के बीच विकल्प नुन्हों की नौबत थी। जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लाखों युवक तरसते हैं, वहां पहुंचने के बाद जिंदगी और मौत का यह संकट पैदा होना अमृतकाल से गुजर रहे देश के लिए कर्तव्य चिंता का विषय नहीं दिखता। डॉ. दिवेश गर्ग के पिता रमेशबंध गर्ग ने पुलिस को दिए आवेदन में एसीआरआर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉ. दिवेश को प्रोफेसर्स द्वारा मानसिक प्रतिष्ठान के कारण आत्महत्या की बात लिखी है। डॉ. दिवेश को 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद लगातार 36 घंटे काम कराया गया और सोने नहीं दिया गया। उसकी शिक्षियों को बार-बार रिकॉर्ड किया गया। मरीजों तथा छात्रों के समने गालियाँ देकर अपमानित किया गया चिरचिर है कि डॉ. दिवेश गर्ग की आत्महत्या वाले दिन ही एक अन्य छात्रा ने भी खुदकुशी का प्रयास किया। लेकिन उसे बचा लिया गया। डॉ. दिवेश जैसी परिस्थितियों से स्टूडेंट्स भी गुजर रहे हैं। लिहाजा, स्टूडेंट्स विरोध में उत्तर आए। जबाब में प्रबंधन ने अभिभावकों को इ-मेल भेजकर डराया। निचली अदालत से फैसला एक आदेश भी ले आया कि काई आदालत नहीं करेगा। देश के जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया में कृच लिखा, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र दिया गया। इससे समाज जा छोड़ने की दिशा द्वारा जिंदगी को संकर्षण करने की नौबत क्यों आ रही है। मेडिकल शिक्षण में दबंगई पर किसी को शोध करना हो, तो यहां से शुरुआत की जा सकती है देश में मेडिकल शिक्षा का नियन्त्रण 'नेशनल मेडिकल कमीशन' (एनएमसी) करता है। यह भी मेडिकल कॉलेजों में आत्महत्याओं से बचाकर है। लिहाजा, मई 2024 में एनएमसी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर एक अनलाइन सर्वेक्षण कराया। मात्र दस दिनों के भीतर 37667 स्टूडेंट्स और फैकल्टी सदस्यों ने इसमें भागीदारी करके स्थिति की भाववहता समाने ला दी है इस सर्वेक्षण के नियत अब तक नहीं आए हैं। लेकिन उस नारकार नहीं करने की शर्त पर एक पीजी स्टूडेंट ने कहा कि यह सर्वेक्षण हमारी असल समस्याओं के बदल परिवारिक वातावरण और अपने परिजनों से मिलने वाले सहजोग पर ज्यादा केंद्रित है। सभव है कि इसकी अनुशंसाओं में स्टूडेंट्स को योगा और मेडिटेशन करने तथा परिस्थितियों का सामना करने संबंधी उपदेश दिया जाएगा। धरवालों को कृच टिप्प दिए जाएं। जबकि असल समस्या मेडिकल कॉलेजों का विषाक्त माहौल है। लगातार काम का दबाव, स्टाइरेंड के भुगतान में धूंधली, तरह-तरह से पैसों की वसूली, सपोर्ट स्टाफ की कमी, प्रोफेसर्स की मनमानी जैसे विषयों पर सर्वेक्षण में गंभीरता नहीं देखने को मिलती है।

खासकर पीजी स्टूडेंट्स को बेहत नारकारी स्थिति में रो-रोकर जीवन जुराने की नौबत आई है। एक स्टूडेंट ने बताया कि 'गायोंनों विभाग में एक बार उसकी लगातार पांच दिनों की कमांडो इयूटी लगी थी। इस दौरान उसे लगातार अस्पताल में ही रहकर वहीं रहना, वहीं खाना और वहीं सोना पड़ा।' एनएमसी ने पीजी मेडिकल एडकेम रेगुलेशन 2023 बनाया। स्टूडेंट्स को उम्मीद थी भारतीय श्रम कानूनों के अनुसार दैनिक आठ घंटे और सासाहिक 48 घंटे कार्यावधि का स्पष्ट नियम बनेगा। लेकिन एनएमसी की नियमावली विल्कुल अस्पष्ट, मनमानी, शोषणपूर्ण और चौंकाने वाली थी। उसमें लिखा गया- सभी पीजी स्टूडेंट पुर्णकालिक रेजिस्टेंट डॉक्टर के रूप में काम करेंगे। वे उचित कार्य घंटों के लिए काम करेंगे। उन्हें एक दिन में आराम के लिए अचित समय प्रदान किया जाएगा।

इसमें काम के अधिकतम घंटों का स्पष्ट निर्धारण नहीं होने के कारण कुछ कॉलेजों में स्टूडेंट्स से औसतन 70 से 90 घंटे तक सासाहिक कार्य करने की शिकायत मिलती हैं। सासाहिक अवकाश का प्रावधान भी अजीब है- कार्य की अत्यावश्यकता के अधीन एक सासाहिक अवकाश की अनुमति दी जाएगी। इसमें सासाहिक अवकाश का प्रावधान भी अधिकार नहीं बनाया गया है बल्कि प्रबंधन की मेहरबानी पर छोड़ दिया गया है एक पीजी स्टूडेंट ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि इंटरनेशनल लेबर कन्वेन्शन और भारत के प्रावधान के लिए अधिकार नहीं देखने को मिलता है। खासकर पीजी स्टूडेंट्स को बेहत नारकारी स्थिति में रो-रोकर जीवन जुराने की नौबत आई है। एक स्टूडेंट ने बताया कि 'गायोंनों विभाग में एक बार उसकी लगातार पांच दिनों की कमांडो इयूटी लगी थी। इस दौरान उसे लगातार अस्पताल में ही रहकर वहीं रहना, वहीं खाना और वहीं सोना पड़ा।' एनएमसी ने पीजी मेडिकल एडकेम रेगुलेशन 2023 बनाया। स्टूडेंट्स को उम्मीद थी भारतीय श्रम कानूनों के अनुसार अत्यधिक काम के दबाव पर आश्रित प्रशिक्षण का यह तरीका अमेरिका के एक डॉक्टर के प्रयोग पर आधारित है। मेडिकल शिक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। डॉ. विलियम स्टीवर्ट हैलस्ट्रेड भोजन और नींद के बीच लगातार लंबे समय तक काम करते रहते थे। वह अपने साथ काम करने वाले प्रशिक्षु डॉक्टरों को भी अपनी तरह लगातार काम करते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद पता चला कि वह कोकीन और अफैम के लिए काम करते थे। इसके प्रभाव में वह लंगूल क्यों नहीं होता। क्या युग्रीन का स्वतः संज्ञान वर्षों से फूट रहा है? एक अन्य पीजी मेडिकल स्टूडेंट के अनुसार अत्यधिक काम के दबाव पर आश्रित प्रशिक्षण का यह तरीका अमेरिका के एक डॉक्टर के प्रयोग पर आधारित है। मेडिकल शिक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। डॉ. विलियम स्टीवर्ट हैलस्ट्रेड भोजन और नींद के बीच लगातार लंबे समय तक काम करते रहते थे। वह अपने साथ काम करने वाले प्रशिक्षु डॉक्टरों को भी अपनी तरह लगातार काम करते थे। लेकिन उनकी मौत के जाती हैं? उन स्टूडेंट ने यह अपने खास फैसलों की भी भाँति अपने खास फैसलों की पैसें देखा। जबकि उन्हें एक रेजिस्टेंट डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल शिक्षण में दबाव और शोषण की परंपरा को खूब बढ़ा देती है। सास भी कभी बहु थीं वाला सिलसिला बढ़ करना होता है। जिन लोगों ने पहले ऐसे विषाक्त काम होता है, वे लोग खुद प्रोफेसर या विभागाध्यक्ष बनने के बाद छात्रों से वैसा ही सलतुक करते हैं। जबकि उन्हें तो ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। गायोंनों फाइनल इयर की एक स्टूडेंट ने कहा कि कई घंटों तक लगातार काम करने का महिमान नहीं होता। यह गलत धारणा बनी हुई है कि इसका उल्लेख किया जाए। उसने कहा कि यह गलत धारणा के लिए एक रेजिस्टेंट डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा धारणा भी नहीं होता। यह गलत धारणा बनी हुई है कि इसका उल्लेख किया जाए। पांच घंटों तक लगातार काम करने का महिमान नहीं होता। यह गलत धारणा बनी हुई है कि इसका उल्लेख किया जाए।



भस्म आरती में नया मुकुट
पहनकर सजे बाबा
महाकाल, आंकड़े की पहनी
माला, आम का लगाया गया
भोग

अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत, नए निजाम में स्थिरता से रप्तार में बढ़ोत्तरी की उम्मीद

इन दिनों प्रकाशित हो रही राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों और विभिन्न बाजार विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने के जो शुभ संकेत उपभक्त दिखाई दे रहे हैं, उन्हें चार जून के बाद नई स्थिर सरकार से आर्थिक पंख लग जाएंगे। ऐसे मजबूत आर्थिक परिदृश्य की संभावनाओं के तीन महत्वपूर्ण कारण गिनाए जा रहे हैं। एक भारत के वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों के दमदार बहु-खाते। दो रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार को दिया गया रिकॉर्ड लाभांश और तीन शेयर बाजार की रिकॉर्ड उचिती।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर 6.8 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक ने 6.6 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, विकास दर 7 प्रतिशत रह सकती है। देश के प्रमुख अर्थव्यवस्थों का मत है कि जहां पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर सात प्रतिशत से अधिक है, वहीं यह आगामी दशक तक 6.5 से 8.5 प्रतिशत रहेगी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, भारत में वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट दिखाई देगा। रिकॉर्ड बैंक के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 17.7 फीसद

04 जून को होगी देवास संसदीय क्षेत्र में मतगणना लगेंगे 122 टेबलों... होंगे 155 राउंड

भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ। शाजापुर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋबु बाफाना ने बताया कि 04 जून 2024 को संसदीय क्षेत्र 21 देवास को आठों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए मतगणना स्थलों पर कुल 122 टेबलें लगाई जाएंगी, जिस पर कुल 2309 मतदान केंद्रों के मतों की गणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। प्रातः जानकारी के अनुसार शाजापुर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में



होने वाली मतगणना के लिए शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 तथा शुजालपुर एवं कालापीपाल क्षेत्र के लिए 14-14 टेबलें लगाई जाएंगी। इसी तरह शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीधेरोड में होने वाली मतगणना के लिए 8 टेबलें लगाई जाएंगी।

शाजापुर में मतगणना के उपरांत वेयर हाउस में रखी जाएगी ईच्छीएम मरीन

भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ।

शाजापुर, लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 21 देवास अंजा में लगने वाली जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र 167 शाजापुर, 168 शुजालपुर एवं 169 कालापीपाल की मतगणना 04 जून 2024 को

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन लड़ने वाले अध्यर्थीयों से स्वयं अध्यर्थी/निर्वाचन अधिकर्ता या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ईच्छीएम परिवहन एवं कोषालय में रखी जाएंगी। इसके साथ ही शिल्ड लिफाफे जिला कोषालय के कक्ष में रखे जाएंगे। संयुक्त

गर्मी का दृश्यभाव न हो एवं उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन बच्चों की उपस्थित हेतु का समय प्रातः 8.30

बजे से सुबह 11.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। महिला एवं बाल विकास प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम चौहान ने बताया कि

एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि कलमकार अब उच्च जीवन मूल्यों के रक्षक योद्धा न रहकर निहित स्वार्थ पूर्ति के लिए इन्हे नष्ट करने वाले कुक्रों का हिस्सा बनने में देर ही नहीं लगते बल्कि और सत्य वह हित की रक्षक कलम की धार को भी कुंद कर बैठते हैं। इसके विपरीत यह भी सत्य है कि दुर्धर्ष संघीयों और उच्च जीवन मूल्यों से समझौतों के इस युग में भी उच्छृंखला करते हुए विकारिता के पैनेपन के सामने सभी लोग न नमस्तक होते हैं। पत्रकारिता दिवस के बाद तक पत्रकारिता के जीवन मूल्यों के युग में पत्रकारिता के समाज को भूमिका को याद करने का दिन

उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

के साथ साथ हित क्यानिंग की दिशा

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

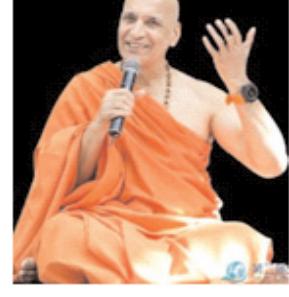
दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता



सत्यनिष्ठ पत्रकारिता सदैव अभिनंदनीय

नहीं बल्कि पत्रकारिता से उच्छृंखला जीवन मूल्यों की रक्षा और सर्वकल्याणार्थ निर्भीक व सत्यनिष्ठ पत्रकारिता की ओर लौटने के संकल्प दिवस के रूप में मनाए जाने की ज़रूरत है। 1970 से करीब दो दशकों तक सक्रिय पत्रकार और प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वर्तमान में भी भारत सरकार के इंटरनेशनल मीडिया अवार्ड कमेटी की ज़्यूरी रहे होंगे युग गुरु स्वामी भारत भूषण ने गर्व से इस और ध्यानांकण किया कि आज भी खुद किसी मजबूरी में ब्रेष्ट पत्रकारिता के आदर्शों से समझौता करके जीवन की धार की धार कर बैठते हैं। इसके विपरीत यह भी सत्य है कि दुर्धर्ष संघीयों और उच्च जीवन मूल्यों से समझौतों के इस युग में भी उच्छृंखला करते हुए विकारिता के पैनेपन के सामने सभी लोग न नमस्तक होते हैं। पत्रकारिता दिवस के बाद तक पत्रकारिता के जीवन मूल्यों के युग में पत्रकारिता के समाज को भूमिका को याद करने का दिन

उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

पत्रकारिता के समाज को

क्रांतिकारी हितकर दिशा देने वाले

उन उच्च मानकों की पुरुषांशुपता

नहीं है, ऐसे में पर्यावरण के

कथन व घटनाओं की पारदर्शिता

देना रही। आज व्यवसायीरकरण की

दौड़ में दिनोंदिन टूटते पत्रकारिता

के जीवन मूल्यों के युग में

